



न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, सोमवार 27 सितंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए || वर्ष-04, अंक- 02

महत्वपूर्ण एवं खास

उरी एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना के 3 जवान घायल

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को सतर्क सैनिकों ने नाकाम कर दिया। इस दौरान सेना के तीन जवान घायल हो गए। रक्षा सूत्रों ने कहा कि सतर्क सैनिकों ने बीती शाम उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की। सूत्रों ने कहा, घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों और सेना के बीच एक मुठभेड़ हुई जिसमें 3 सैनिक घायल हो गए। इलाके में अभियान अभी भी जारी है। घायल हुए तीन जवान 12 जाट रेजीमेंट के हैं। उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले 18 सितंबर को, उसी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की एक और बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया था।

मोतिहारी में हुआ बड़ा हादसा, नाव पलटने से नदी में डूबे 22 लोग, 6 के शव बरामद

मोतिहारी (आरएनएस)। बिहार के मोतिहारी में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां सिकरहना नदी में नाव पलटने से 22 लोग डूब गए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक 6 शव बरामद हुए हैं। शिकारगंज थाना अध्यक्ष के अनुसार अब तक एक बच्ची का शव नदी से निकाला गया है जिसकी पहचान चांदनी कुमारी के रूप में की गई है। नाव पलटने की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना के बाद घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई है। जानकारी के अनुसार मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम लोगों को निकालने में जुटी है। वहीं स्थानीय गोताखोर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि नाव चला रहा व्यक्ति तैर कर बाहर निकलने में कामयाब रहा। मौके पर व्यापक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं।

भारत में कोविड-19 के कुल टीकाकरण कवरेज ने 85 करोड़ का ऐतिहासिक पड़ाव किया पार

नई दिल्ली (आरएनएस)। 24 घंटों में 68,42,786 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 85 करोड़ (85,60,81,527) के ऐतिहासिक पड़ाव के पार पहुंच गया। इस उपलब्धि को 83,64,110 टीकाकरण सत्रों के जरिये हासिल किया गया है। पिछले 24 घंटों में 26,032 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों (महामारी की शुरुआत के बाद से) की कुल संख्या बढ़कर 3,29,02,351 हो गई है। नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.77% है। स्वस्थ होने की दर मार्च, 2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है। केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 91 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वर्तमान में 3,03,476 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.90% हैं। देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,88,945 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 56.32 करोड़ (56,32,43,245) जांच की गई हैं। देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.98 प्रतिशत है जो पिछले 93 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.90 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 27 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 110 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।

ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से आज गुजरेगा गुलाब तूफान

अमरावती (आरएनएस)। ओडिशा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तटों के बीच से रविवार को गुलाब चक्रवात के गुजरने की आशंका है जिसके महेनजर बचाव और राहत कार्यों के लिए उत्तर तटीय और राहत कार्यों के लिए उत्तर तटीय (एनडीआरएफ) के तीन और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के एक दल को तैनात किया गया है। वहीं, ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल (ओडीआरएफ) के 42 दलों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के 24 दलों के साथ दमकल कर्मियों को सात जिलों गजपति, गंजम, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, कंधमाल भेजा है। सरकार की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में निचले इलाकों से लगभग शिफ्ट करने की योजना बनाई

गई है। श्रीकाकुलम में एनडीआरएफ के दो दलों को तैनात किया गया है जहां चक्रवात का अधिक प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा विशाखापत्तनम में एक दल को तैनात किया गया है। विशाखापत्तनम में एनडीआरएफ के एक दल को भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। राज्य आपदा आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के एक दल को तैनात किया गया है। वहीं, ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल (ओडीआरएफ) के 42 दलों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के 24 दलों के साथ दमकल कर्मियों को सात जिलों गजपति, गंजम, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, कंधमाल भेजा है। सरकार की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में निचले इलाकों से लगभग शिफ्ट करने की योजना बनाई

गई है। श्रीकाकुलम में एनडीआरएफ के दो दलों को तैनात किया गया है जहां चक्रवात का अधिक प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा विशाखापत्तनम में एक दल को तैनात किया गया है। विशाखापत्तनम में एनडीआरएफ के एक दल को भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। राज्य आपदा आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के एक दल को तैनात किया गया है। वहीं, ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल (ओडीआरएफ) के 42 दलों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के 24 दलों के साथ दमकल कर्मियों को सात जिलों गजपति, गंजम, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, कंधमाल भेजा है। सरकार की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में निचले इलाकों से लगभग शिफ्ट करने की योजना बनाई

गई है। श्रीकाकुलम में एनडीआरएफ के दो दलों को तैनात किया गया है जहां चक्रवात का अधिक प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा विशाखापत्तनम में एक दल को तैनात किया गया है। विशाखापत्तनम में एनडीआरएफ के एक दल को भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। राज्य आपदा आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के एक दल को तैनात किया गया है। वहीं, ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल (ओडीआरएफ) के 42 दलों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के 24 दलों के साथ दमकल कर्मियों को सात जिलों गजपति, गंजम, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, कंधमाल भेजा है। सरकार की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में निचले इलाकों से लगभग शिफ्ट करने की योजना बनाई

प्रेमिका से रिश्ते रखते हुए ऐन वक्त पर शादी से इनकार करना रेप नहीं : हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला औरंगाबाद (आरएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ ने रेप के मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर कोई शख्स प्रेमिका से रिश्ते रखने के बाद ऐन वक्त पर शादी से इनकार करता है, तो वह रेप नहीं कहलाएगा। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़िता की ओर से जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, उनके आधार पर यह साबित होता है कि आरोपी ने बलात्कार किया है। आरोपी ने बाद में शादी का खयाल भले ही बदल लिया हो, लेकिन पहले आरोपी से इरादा महिला से शादी करने का था। दरअसल तीस वर्षीया महिला ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और फरेब का केस दर्ज किया था। पीड़िता की ओर से की गई शिकायत में यह दावा किया गया था कि आरोपी ने शादी का वादा किया, जिसके बाद दोनों परिवार के सदस्य मिले। इस दौरान भी आरोपी ने शादी से इनकार नहीं किया। शादी तय होने के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। इसी बीच कोरोना के चलते शादी टल गई। लेकिन कोरोना काल खत्म होने के बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुनील देशमुख और न्यायमूर्ति नितिन सूर्यवंशी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपने फौसले में कहा कि जब दोनों परिवारों की मुलाकात हुई तो आरोपी ने शादी के लिए राजमंदी दिखाई थी। जो दोनों के बीच शारीरिक संबंध हुए वे एक दूसरे के बीच प्यार होने की वजह से हुए और आपसी सहमति से हुए। बाद में प्रेमी का मन बदल गया और उसे अब शादी में कोई रुचि नहीं है। शादी का केस दर्ज किया था।

विश्व नदी दिवस पर पीएम मोदी ने बताया नदियों का महत्व, लोगों से की साथ मिलकर काम करने की अपील

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 81वें संस्करण में राठ को संबोधित कर रहे हैं। सितंबर महीने का एपिसोड प्रधानमंत्री की हाल की संयुक्त राठ (अमेरिका) यात्रा के बाद आया है। अमेरिका में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और चाड रूफिंग के अन्य सदस्यों से मुलाकात की, और संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) को संबोधित किया। विश्व नदी दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास में नदियों की भूमिका को स्वीकार करते हुए राठ के नाम अपने संबोधन की शुरुआत की और लोगों से देश की कई नदियों को प्रदूषित न करने का आग्रह किया। मन की बात पर पीएम नरेंद्र

तीन नए कृषि कानून का मामला : आज किसानों ने किया भारत बंद का ऐलान

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा लाये गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने सोमवार यानी 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कल होने वाले भारत बंद को देशभर के 40 किसान संगठनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में देशभर के तमाम किसान संगठन हर राज्यों में जनसभाएं कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह भारत बंद में किसानों का साथ दें और



उनका समर्थन करें। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि कर्मचारी यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन समेत कई संस्थाओं के भारत बंद को पहले ही अपनी सहमति दे दी है। मोर्चा ने कहा कि बंद का आयोजन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में

सड़कों से नहीं हटेंगे। क्या खुला-क्या बंद संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं के मुताबिक पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को हटाने की कार्रवाई की तो किसान जेल जाना पसंद करेंगे लेकिन सड़कों से नहीं हटेंगे। इसी दौरान प्राइवेट दफ्तर, शिक्षण संस्थान, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बंद के दौरान एंजुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज को नहीं रोका जाएगा। इसी तरह मालवाहक ट्रकों और गाड़ियों को दिल्ली से आने या जाने नहीं दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री आज पीएम डिजिटल स्वास्थ्य अभियान का करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली (आरएनएस)। एक ऐतिहासिक पहल के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर, 2021 को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य अभियान (पीएम-डीएचएम) का शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात, प्रधानमंत्री इस अवसर पर अपना संबोधन भी देंगे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2020 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। वर्तमान में, पीएम-डीएचएम छह केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक चरण में लागू किया जा रहा है। पीएम-डीएचएम का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ एनएचएम की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) की तीसरी वर्षगांठ के साथ ही किया जा रहा है। इस अवसर पर



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (पीएम-डीएचएम) के बारे में जन धन, आधार और मोबाइल (जेएम) ट्रिनिटी और सरकार की अन्य डिजिटल पहलों के रूप में तैयार बुनियादी ढांचे के आधार पर, पीएम-डीएचएम स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता को सुनिश्चित करते हुए एक

विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान के माध्यम से डेटा, सूचना और जानकारी का एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जिससे बुनियादी ढांचा सेवाओं के साथ-साथ अंतर-प्रचालनीय और मानक-आधारित डिजिटल प्रणाली का विधिवत लाभ उठाया जा सकेगा। इस अभियान के अंतर्गत नागरिकों की सहमति से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान-प्रदान को सक्षम बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री-डीएचएम के प्रमुख घटकों में प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी शामिल है जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी कार्य करेगी, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से जोड़ा और देखा जा सकता है। इसके तहत, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एचपीआर) और हेल्थकेयर

फैसिलिटीज रजिस्ट्रियां (एचएफआर), आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों दोनों ही मामलों में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक संग्रह के रूप में कार्य करेंगी। यह चिकित्सकों/अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए व्यवसाय में भी आसानी को सुनिश्चित करेगा। अभियान के एक हिस्से के रूप में तैयार किया गया पीएम-डीएचएम सैंडबॉक्स, प्रौद्योगिकी और उत्पाद जांच के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करेगा और ऐसे निजी संगठनों को भी सहायता प्रदान करेगा, जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य निरोधन का हिस्सा बनते हुए स्वास्थ्य सूचना प्रदाता या स्वास्थ्य सूचना उपयोगकर्ता अथवा पीएम-डीएचएम के तैयार ब्लाक्स के साथ कुशलता से स्वयं को जोड़ने की मंशा रखते हैं।

जम्मू-कश्मीर में 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे : सिधिया

श्रीनगर (आरएनएस)। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिधिया ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही दो नए एयरपोर्ट टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने यह बात श्रीनगर जिले के हर्वा ब्लॉक में डीडीसी, बीडीसी सदस्यों, पीआरआई और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कार्यक्रम के दौरान कही। एक बड़े विकास के रूप में, मंत्री ने कहा कि कश्मीर में 25,000 वर्ग मीटर पर 1,500 करोड़ रुपये का एक हवाईअड्डा टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, जबकि जम्मू में 22,000 वर्ग मीटर भूमि पर 650 करोड़ रुपये का एक अन्य हवाईअड्डा टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चूंकि जम्मू और कश्मीर में हवाई और सड़क संपर्क दोनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में राजमार्गों, रिंग रोड, सुरंगों और अन्य परियोजनाओं सहित एक प्रमुख सड़क नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी के विकास से जम्मू-कश्मीर में अधिक पर्यटक आएंगे और स्थानीय शिल्प को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन और शिल्प को बढ़ावा देने से जम्मू-कश्मीर के लोगों की आर्थिक गतिविधियों और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल पर एक महीने में 1.7 करोड़ से अधिक हुआ पंजीकरण

नई दिल्ली (आरएनएस)। असंगठित क्षेत्र और असंगठित रोजगार में 1.71 करोड़ से अधिक श्रमिकों के पंजीकरण के साथ ई-श्रम पोर्टल ने अपने शुभारंभ का एक माह पूरा कर लिया है। 25 सितंबर तक पोर्टल पर 1,71,59,743 श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्घाटन 26 अगस्त, 2021 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे। पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, जीआईजी और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का यह पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। यह

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। उपयुक्त आंकड़े पंजीकरण कार्य की साप्ताहिक प्रगति को दर्शाते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, प्रत्येक सप्ताह व्यापक रूप से उपलब्ध को अर्जित करने के अलावा श्रमिकों की लामबंदी के साथ यह अभियान और परिपुष्ट हुआ है। 19.52 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ दूसरे सप्ताह में तुलना में तीसरे और चौथे सप्ताह में पंजीकरण तेजी से बढ़ा। चौथे सप्ताह में 69.53 लाख से अधिक श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया। इस अभियान को गति देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार एवं पर्यावरण,



वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल महाराष्ट्र के मुंबई में असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड वितरित किए। यादव ने कोविड-19 से अपनी जान गंवाने वाले श्रमिकों के आश्रितों को ईएसआई कोविड-19 राहत योजना के लिए अनुमोदन पत्र और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अटल बीमिष्ठ व्यक्ति कल्याण योजना

राहत स्कीम के अनुमोदन पत्र भी भेंट किए। ई-श्रम पोर्टल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्री महोदय ने असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक श्रमिक का पोर्टल पर पंजीकरण होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंजीकरण आवश्यक है, ताकि हम जान सकें कि प्रत्येक व्यवसाय में कितने श्रमिक हैं। पोर्टल पर पहले ही 400 से अधिक व्यवसायों का प्रतिनिधित्व किया जा चुका है। हम चाहते हैं कि सभी लोग पंजीकरण कराएं ताकि छोटे से छोटे कार्य करने सहित हर श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिक अब 2 लाख रुपये तक का बीमा प्राप्त करने के पात्र हैं। यादव ने व्यापार संघों के नेताओं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं के साथ भी वार्तालाप करते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) डी.पी.एस. नेगी और मुंबई के केंद्रीय उद्योग श्रम आयुक्त तेज बहादुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। नेगी ने कहा कि पोर्टल को सफल बनाने में राज्य सरकारों, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जीआईजी श्रमिकों को रोजगार देने वाली एएं आधारित सेवाओं, असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं की भी बड़ी भूमिका होगी। आयुक्त ने

उल्लेख करते हुए कहा कि 'सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास' जैसी प्रधानमंत्री की शासन परिकल्पना के अनुरूप, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए श्रमिकों के विश्वास के साथ-साथ सभी हितधारकों के प्रयासों की भी आवश्यकता है। माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 सितंबर, 2021 महाराष्ट्र के मुंबई में असंगठित श्रमिकों को अटल बीमिष्ठ व्यक्ति कल्याण योजना राहत स्कीम एवं ई-श्रम कार्ड हेतु स्वीकृति पत्र वितरित किये तथा व्यापार संघों के नेताओं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं नियोक्ताओं से वार्तालाप किया।